



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
ART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 411] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 1982/भाद्र 24, 1904
No. 411] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 15, 1982/BHADRA 24, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर 1982

का० प्र० 668(प्र)/18-बख/उ० वि० वि० सं०/82 —केंद्रीय सरकार
ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 15)
की धारा 18-बख की उपधारा (1) ब खड (क) और (ख) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० प्र० 39 (प्र)/18-बख
/उ० वि० वि० सं०/77, तारीख 22 जनवरी 1977 द्वारा (जिस हममें
हमके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) यंत्र घाषणा की थी कि —

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), इस
अनुकूल संहिता की उक्त अधिनियम की धारा 3-क के अध्याय
5-क और 5-ख और धारा 33 ग का लोप किया जाएगा,
जैसा बंगाल पाटरोज निमिटेड, कलकत्ता के स्वामित्वार्थन दो
औद्योगिक उपक्रमों को लागू होगा, और

(घ) राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व
प्रबल ऐसा सभी सविधाना, संपात के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों,
व्यवस्थापना, पचाटा स्थानों आदेशों या अन्य लिखतों का
प्रवर्तन (जिस भिन्न लिखत) सबध बैंको और वित्तीय संस्थाओं के
प्रतिभूत दायित्वों से है), जिनके उक्त औद्योगिक उपक्रमों के
पक्षकार है या ऐसे औद्योगिक उपक्रमों की स्वामी बननी पक्षकार है
या जो सम्बन्धित उन औद्योगिक उपक्रमों या कर्मों की लागू

होत है, और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या
उद्भूत सभी या कोई अधिभार, विशेषाधिकार बाध्यता और
शायित्व निरुद्धि रहेगे,

और उक्त आदेश का अधि गमय-ममय पर और 14 सितम्बर,
1982 तक के लिये जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई था,

और केंद्रीय सरकार का समाधान हा गया है कि उक्त आदेश की
अधि 14 मार्च, 1983 तक के लिये जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है,
बढ़ा दी जानी चाहिए,

अतः अब, केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम,
1951 (1951 का 15) की धारा 18-बख की उपधारा (2) के साथ
पठित उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, उक्त अधि 14 मार्च, 1983 तक के लिये जिसमें
यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[का० सं० 2 (19)/75-सं० यू० एम०]
ए० पी० मन्थन, सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 15th September, 1982

S.O. 668(E)/18FB/IDRA/82.—Whereas by the Order of
the Government of India in the Ministry of Industry (De-
partment of Industrial Development) No. S.O. 39(F)/18FB/
IDRA/77, dated the 22nd January, 1977 (hereinafter re-

d to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section 1 of section 18-B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that :—

- (a) the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), shall apply to the two industrial undertakings owned by Messrs Bengal Potteries Limited, Calcutta, with the adaptations that section 9A, Chapters, VA and VB and section 33C of the said Act shall be omitted, and
- (b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions), to which the said industrial undertakings are parties, or the company owning such industrial undertakings is a party or which may be applicable to the industrial under-

takings or the company, as the case be, and all or any of the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended;

And whereas, the duration of the said Order was extended from time to time upto and inclusive of the 14th September, 1982.

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said order should be extended for a further period upto and inclusive of the 14th March, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1), read with sub-Section (2) of section 18-B of the Industries Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order up to and inclusive of the 14th March, 1983.

{File No. 2(19)/75-CUS}
A. P. SARWAN, Jt. Secy